

करो गब्बा भुगतान वरना चीनी उठाएंगे किसान

बीएस संवाददाता

नई दिल्ली/लखनऊ 29 नवंबर

यूपी के किसान आक्रोशित



लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज, मिल के गार्ड ने की हवाई फायरिंग

31 चीनी मिलों में

पेराई शुरू

24 सौ करोड़ रु.

मिलों पर बकाया

■ किसानों ने कहा कि राज्य सरकार मिलों का अधिग्रहण कर शुरू करे पेराई

■ केंद्र व राज्य सरकारों पर किसानों की अनदेखी का आरोप

गाने की पेराई शुरू न होने से सड़कों पर उतरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने आज चीनी मिलों को पिछले साल का भुगतान करने के लिए शनिवार तक समय दिया है। भुगतान न होने की स्थिति में किसान चीनी मिलों से चीनी उठाने की धमकी दे रहे हैं। निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध ने किसानों को उत्तेजित कर दिया है। कल लखीमपुर में गन्ना किसान की आत्महत्या को लेकर उत्तेजित किसानों ने आज गुलरिया चीनी मिल के गेट पर हिंसक प्रदर्शन किया। किसानों ने अपने मृत साथी के शव को मिल गेट पर रख कर जाम लगा दिया।

प्रदर्शन के बीच किसानों ने पथरबाजी की और मिल के गेट को जबरदस्ती खुलवाने का प्रयास किया। मिल के सुरक्षा गार्डों ने उत्तेजित किसानों को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई। किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी और हल्का लाठीचार्ज भी किया। पुलिस और किसानों के बीच हुए इस संघर्ष में एक किसान को चोट भी आई है।

उधर कुछ किसान आज शामली में एक चीनी मिल पर बकाया भुगतान

के बसौली के गन्ना किसान सत्यपाल सिंह ने आत्महत्या कर ली। गन्ना किसान कर्ज में डूबा था और पेराई शुरू न होने से परेशान था। हालांकि जिला प्रशासन ने किसान की मौत का कारण बीमारी बताया है पर गांव वालों के मुताबिक उस पर काफी कर्ज था और बीते साल के गन्ना बकाए के भुगतान न होने से वह परेशान था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री ने किसानों पर बल प्रयोग और फायरिंग की निंदा की है। उनका कहना है कि सरकार किसानों के बकाया भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है।

इस बीच आज सरकार ने 31 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो जाने का दावा किया है। आज निजी क्षेत्र की मसौथा चीनी मिल में गन्ना पेराई की शुरुआत हो गई। चीनी मिल के चेयरमैन लक्ष्मीकांत झुनझुनवाला से जिला प्रशासन ने वार्ता कर चीनी मिल में पेराई आज चालू कराया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 31 चीनी मिलों में पेराई का काम शुरू हो चुका है। इनमें सहकारी क्षेत्र की 24 में से 22 चीनी मिलें, चीनी निगम की एक और निजी क्षेत्र की 8 चीनी मिलें शामिल हैं। निजी क्षेत्र की जिन चीनी मिलों में पेराई की शुरुआत हो गई है उनमें इंडियन पोटाश लिमिटेड की पांच, वेब समूह की एक, झुनझुनवाला की एक और पारले समूह की एक चीनी मिल शामिल हैं।

चाहिए। अगर कल तक गन्ने का भुगतान नहीं होता तो किसान मिलों से भुगतान के अचूक चीनी का स्टॉक उठा लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर निजी चीनी मिल मालिक मिल नहीं चलाना चाहते हैं तो सरकार मिलों का अधिग्रहण कर मिस चलाए। मिल चलाए जाने पर अगर नुकसान होता है तो किसान उसके हिस्सेदार बनने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का करीब 2400 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान है।

गौरतलब है कि कल लखीमपुर जिले

महाराष्ट्र में मिलों को राहत

संजय जोग

मुंबई, 29 नवंबर

स्वाधिपानी संगठन (एसएसएस) के आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद महाराष्ट्र चीनी उद्योग को राहत मिली है। संगठन ने अगले साल जनवरी माह तक आंदोलन को रोकने का निर्णय लिया है। संगठन गन्ने की अधिक कीमत दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। कोल्हापुर जिले के एक चीनी सहकारी समिति द्वारा कल 2.650 रुपये प्रति टन अग्रिम कीमत की घोषणा किए जाने के बाद एसएसएस ने अपने आंदोलन को वापस लिया है।

पिछले 48 घंटों तक चलने वाले इस आंदोलन ने हिंसक रूप अखियार कर लिया था जब एसएसएस कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको की शुरुआत करते हुए कथित तौर पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों को आग लगा दी थी। एसएसएस के प्रमुख और लोकसभा सांसद राजू शेट्टी ने सभी चीनी संयंत्रों से प्रति टन गन्ना के

लिए 2,650 रुपये दिए जाने की मांग की थी। गन्ने की कीमत का भुगतान दो किस्तों में किया जाना था जिसमें तत्कालिक तौर पर 2,200 रुपये प्रति टन की रकम का भुगतान किया जाना था जबकि दो से तीन महीने के बाद बची हुई 450 रुपये की रकम का भुगतान किया जाना था। उन्होंने कहा कि उनका संगठन 31 दिसंबर तक इंतजार करेगा और अगर चीनी उद्योग भुगतान करने में असफल रहता है तो अगले साल जनवरी माह से नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। शेट्टी का संगठन और अन्य किसानों के संगठन ने गन्ने की अधिक कीमत की मांग को लेकर एक महीने पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। शेट्टी प्रति टन 3,000 रुपये की मांग कर रहे थे जबकि रघुनाथदादा पाटिल का संगठन शेतकारी संगठन प्रति टन 3,500 रुपये की मांग कर रहा था। हालांकि चीनी उद्योग ने प्रति क्विंटल 2,600 रुपये से लेकर 2,650 रुपये की मौजूदा कीमत का हवाला देते हुए अधिक कीमतों के भुगतान को लेकर असमर्थता जताई थी।

Business Standard

30/11/13